महाप्रबंधक, दूरसंचार, जबलपुर के कार्यालय के लिये किराये पर ली गई इमारत

*235. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में जबलपुर स्थित दूरसंचार जिला प्रबंधक का कार्यालय, जिसे वहां महाप्रबंधक की तैनाती हो जाने के बाद अब महाप्रबंधक के कार्यालय के नाम से जाना जाता है, एक किराये की इमारत में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय इस इमारत में कब से चल रहा है; और

(ग) इस इमारत हेतु प्रतिमाह कितने किराए का भुगतान किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) 1.5.1992 से

(ग) 35,600 /- रु०

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु मानदंड

*236. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन मानदण्डों का पालन नहीं किया जा रहा है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ): (क) अब तक रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपनाये गये मानदंड के अनुसार सुविधाओं को "मूल सुविधाएं" और "अतिरिक्त सुविधाएं" नामक दो कोटियों में विभाजित किया जाता था, मूल सुविधाएं वे न्यूनतम सुविधाएं थीं जो सभी स्टेशनों पर मुहैय्या की जानी अपेक्षित थीं "अतिरिक्त सुविधाएं" वे सुविधाएं थीं जो एक स्टेशन पर "मूल सुविधाओं" के रूप में सूचीबद्ध सुविधाओं के अलावा मुहैय्या की गई थी "अतिरिक्त सुविधाओं" की व्यवस्था सतत् आधार पर की जाती थी जो प्रत्येक स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात के महत्व और यात्रा पर आधारित थी, परन्तु ये सुविधाएं धन की समग्र उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती थीं मूल सुविधाओं में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल थीं:—

नियमित/फ्लैग स्टेशनों पर

1. समुचित बुकिंग व्यवस्था
2. प्रतीक्षालय
3. बेंच
4. रोशनी का उपयुक्त प्रबंध
5. पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था
6. भली प्रकार अनुरक्षित सतह वाले प्लेटफार्म
7. शौचालय, और
8. छायादार वृक्ष

हाल्ट स्टेशनों पर

1. बुकिंग-एवं-प्रतीक्षा शेड
2. स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों की लंबाई के अनुरूप लंबाई वाला पटरी की सतह वाला एक प्लेटफार्म
3. जहां रात्रि में गाड़ियां रुकती हैं वहां रोशनी की व्यवस्था
4. छायादार वृक्ष

(ख) इस मानदंड का सभी रेलों द्वारा एक समान रूप से पालन किया गया है। बहरहाल, रेलों से संबंधित संसद की स्थाई समिति ने "मूल" और "अतिरिक्त" सुविधाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं।

रेलवे की लागत नियंत्रण योजना

*237. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पास कोई लागत नियंत्रण योजना नहीं है जिसके कारण परियोजना लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने टाटा कंसल्टैंसी द्वारा तैयार किए गये साफ्टवेयर पैकेज, जो लागत नियंत्रण में काफी लाभदायक है, के संबंध में कोई जांच की है; और